P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-1* ISSUE-12* March- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

डिजिटल इंडिया : नौ स्तम्भ

अनिता खुराना
व्याख्याता,
संस्कृत विभाग,
स.पृ.चौ. राज. महा.,
अजमेर

सारांश

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका आरंभ 1 जुलाई 2015 को हुआ, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल लिहाज से सषक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना है। इसके तहत जिस लक्ष्य को पाने के लिये ध्यान केन्द्रित किया गया है वह है भारतीय प्रतिभा (IT)+ सूचना प्रौद्योगिकी (IT)=कल का भारत(IT)

नौ प्रभावशाली स्तंभ

ब्राडबैण्ड हाइवे, लोक हित पहुंच कार्यक्रम, हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी, ई–क्रान्ति, ई–गर्वनेंस, सभी की सूचना, नौकरी के लिये आई टी, पूर्व फसल कार्यक्रम और इलेक्ट्रानिक विनिर्माण।

डिजिटल इंडिया भारत सरकार की बहु उपयोगी सार्थक पहल है जिससे देश में सभी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, कालाबाज़ारी कम होगी, कागजी कार्य, समय, मानव श्रम की बचत, कार्यकुशलता में सुधार होगा।

मुख्य शब्द : अम्ब्रेला कार्यक्रम (Umbrella Programme)
डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment)
नौ स्तम्भ (Nine Pillars)

प्रस्तावना

मोदी सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक ऐसा अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है तथा यह सुनिश्चित करता है कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाएं मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जनता तक पहुँच सके। इसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जुलाई, 2015 को नई दिल्ली में किया।

केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से आरम्भ किया गया यह महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके निम्न तीन प्रमुख घटक हैं –

1. डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना
2. मांग पर सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आम जनता तक पहुँचाना
3. नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment of Citizen)।

इस लक्ष्य को पाने के लिए जिस पर ध्यान केन्द्रित किया गया है वह है –

भारतीय प्रतिभा (IT) + सूचना प्रौद्योगिकी (IT) = कल का भारत

डिजिटल इंडिया में नौ प्रभावशाली स्तम्भ सम्मिलित हैं – (HIGH JUMKI)

1. ब्राडबैण्ड हाइवे – (Broadband Highway)
2. जन इण्टरनेट पहुँच कार्यक्रम – (Public Internet)
3. ई शासन – (E-Governence)
4. पूर्व फसल कार्यक्रम – (Early Harvest Programme)
5. रोजगार के लिये आई टी – (IT for Jobs)
6. हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी – (Universal access to phones)
7. इलेक्ट्रानिक विनिर्माण – (Electronic Manufacturing)
8. ई–क्रान्ति – (E Kranti)
9. सभी के लिये सूचना – (Information for all)

ब्राडबैण्ड हाइवे – (Broadband Highway)

इसके तहत तीन उपघटकों –

1. सभी के लिये ब्राडबैण्ड – ग्रामीण
2. सभी के लिये ब्राडबैण्ड – शहरी
3- राष्ट्रीय सूचना संरचना (NII)

को सम्मिलित किया गया।

सभी के लिये ब्राडबैण्ड–ग्रामीण

2,50,000 ग्राम पंचायतों को दिसम्बर 2016 तक राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) के तहत कवर किया जायेगा। दूरसंचार विभाग (DOT) इस परियोजना के लिये नोडल विभाग है।

सभी के लिये ब्राडबैण्ड – शहरी

नए शहरी विकास और इमारतों में सेवा वितरण और संचार सुविधाओं को अनिवार्य करने के लिये वर्चुअल नेटवर्क आपरेटरों का उद्यामन किया जायेगा।

राष्ट्रीय सूचना संरचना (NII)

NII देश में पंचायत स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों के लिये उच्च गति कनेक्टिविटी और क्लाउड मंच प्रदान करने के लिये नेटवर्क और क्लाउड अवसंरचना द्वारा एकीकृत होगा। इन अवसंरचना के घटकों में – स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN), राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क (NKN), राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN), सरकारी प्रयोक्ता नेटवर्क (GUN) और मेघराज क्लाउड नेटवर्क शामिल है।

NII का उद्देश्य SWAN, NKN, NOFN, GUN, GI क्लाउड के रूप में सभी ICT अवसंरचना के घटकों को एकीकृत करना है। DITY इस परियोजना में लिये नोडल विभाग होगा।

जन इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम (Public Internet)

पब्लिक इंटरनेट एसेस कार्यक्रम के दो उप घटक –

1. सामान्य सेवा केन्द्र (CSC)
2. बहुसेवा केन्द्र के रूप में डाकघर हैं।

1. सामान्य सेवा केन्द्र (CSC)

सी.एस.सी. को मजबूत किया जायेगा। इसके परिचालन की संख्या वर्तमान में लगभग 1,35,000 से 2,50,000 तक बढ़ जायेगी। सी.एस.सी. को सरकारी और व्यापार सेवाओं के वितरण के लिये व्यवहार्य और बहु आयामी एण्ड–प्वाइट दिया जायेगा। नोडल विभाग – डी. ई.आई.टी.वाई. है। (DEITY)

2. बहु सेवा केन्द्रों के रूप में डाक घर

1,50,000 डाकघरों को बहु सेवा केन्द्रों में तब्दील करने का प्रस्ताव है। नोडल विभाग – डाक विभाग है।

ई–शासन – (E-Governence) प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकारी तंत्र में सुधार

1. **फार्म का सरलीकरण और आकार में कमी** – फार्म को सरल एवं उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाना चाहिए और केवल न्यूनतम और आवश्यक जानकारी एकत्र किया जाना चाहिए।
2. **आनलाइन एप्लीकेशन और ट्रैकिंग** – आनलाइन एप्लीकेशन और स्थिति ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
3. **आनलाइन संग्रह** – प्रमाण पत्र, शैक्षणिक डिग्री, पहचान दस्तावेजों आदि के लिये आनलाइन संग्रह का प्रयोग। जिससे नागरिकों को खुद भौतिक रूप से प्रस्तुत होकर इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता न हो।
4. **सेवाओं और प्लेटफार्मों का एकीकरण** – सेवाओं और प्लेटफार्मों का एकीकरण उदाहरण – भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का आधार प्लेटफार्म, भुगतान गेटवे, मोबाइल सेवा प्लेटफार्म, नागरिकों और व्यवसायों में सेवा डिलिवरी की सुविधा के लिये राष्ट्रीय और राज्य सेवा डिलिवरी गेट वे (NSDG/SSDG) के रूप में ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और मिडलवेयर के माध्यम से डाटा के आदान–प्रदान के लिये इसे एकीकृत और अंत–प्रचालनीय किया जाना चाहिए।
5. सभी डेटाबेस और जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में होना चाहिए। सरकारी विभागों और एजेन्सियों के अंदर कार्य–प्रवाह को सक्षम करने के लिये सरकारी प्रक्रियाओं को स्वचालित किया जाना चाहिए और साथ ही नागरिकों को इन प्रक्रियाओं की दृश्यता की अनुमति देनी चाहिए। आईटी (IT) को स्वचालित रूप से डेटा का विश्लेषण, जवाब और समस्याओं की पहचान करने एवं हल करने के लिये इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे सुधार की प्रक्रिया के लिये इस्तेमाल किया जाएगा।

पूर्व फसल कार्यक्रम (Early Harvest Programme)

पूर्व फसल कार्यक्रम में मूलरूप से उन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है जिन्हें कम समय के भीतर लागू किया जाना है। अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं हैं –

संदेशों के लिए आईटी प्लेटफार्म

मास मैसेजिंग एप्लिकेशन को डीईआईटीवाई द्वारा विकसित किया गया है, जिसके तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों और सभी सरकारी कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। 1.36 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन और 22 लाख ई–मेल इस डेटाबेस का हिस्सा हैं। इस पोर्टल को 15 अगस्त 2014 को जारी किया गया। डेटा संग्रह और डेटा छटाई की प्रक्रियाएं चल रही हैं।

सरकारी शुभकामनाएं ई–शुभकामनाओं के रूप में होंगी

ई–शुभकामना टेम्पलेट्स उपलब्ध कराये गये हैं। **मेरी सरकार** मंच के माध्यम से ई–शुभकामनाओं की समूह सोर्सिंग को सुनिश्चित किया गया है। समूह सोर्सिंग को स्वतंत्रता दिवस, शिक्षक दिवस और गाँधी जयन्ती के अवसर पर ई–ग्रीटिंग्स डिजाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ई–ग्रीटिंग्स पोर्टल को 14 अगस्त 2014 को लाइव किया गया।

बॉयोमैट्रिक उपस्थिति

इसके साथ दिल्ली में केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों को कवर किया जाएगा। 150 संगठनों के 40,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को पहले ही कॉमन बॉयोमैट्रिक उपस्थिति पोर्टल http://attendance.gov.in पर पंजीकृत किया है। 1000 से अधिक बायोमेट्रिक उपस्थिति टर्मिनलों को वाई–फाई एसेस प्वाइंट और मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाएगा। जो विभिन्न केन्द्रीय सरकार के भवनों के प्रवेश गेटवे पर स्थापना के अधीन हैं। सरकारी कर्मचारी दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में से किसी से अपनी उपस्थिति चिह्नित करने में सक्षम हो जाएगे।

सभी विश्वविद्यालयों में वाई–फाई

राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क (एनकेएन) पर सभी विश्वविद्यालयों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) इस योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

सरकार के भीतर सुरक्षित ई–मेल

ई–मेल सरकार के भीतर संचार का प्राथमिक मोड़ होगा। सरकारी ई–मेल की अवसंरचना को बढ़ाया और उन्नत किया जाएगा। 10 लाख कर्मचारियों के लिए पहले चरण के तहत बुनियादी ढांचे के उन्नयन को पहले ही पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण के तहत, अवसंरचना को 98 करोड़ रुपये की लागत से मार्च 2015 तक 50 लाख कर्मचारियों को कवर करने के लिए उन्नत किया जाएगा। डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल विभाग है।

सरकारी ई–मेल डिजाइन का मानकीकरण

सरकारी ई–मेल के लिए मानकीकृत टेम्पलेट्स तैयार रहना होगा। इसे डीईआईटीवाई द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट

1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और पर्यटन केन्द्रों में डिजिटल शहरों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक वाई–फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराया जाएगा। योजना को डीओटी और शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा लागू किया जाएगा।

विद्यालयी पुस्तकों की ई–पुस्तकों के रूप में उपलब्धता

सभी किताबों को ई–बुक में परिवर्तित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय/डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल एजेंसियाँ हैं।

एसएमएस आधारित मौसम की जानकारी, आपदा अलर्ट

एसएमएस आधारित मौसम की जानकारी और आपदा अलर्ट मुहैया कराई जाएगी। डीईआईटीवाई की मोबाइल सेवा प्लेटफार्म को इसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराया गया है। भू–विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) (भारतीय मौसम विभाग – आईएमडी)/गृह मंत्रालय (एमएचए) (राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–एनडीएमए) इस योजना को लागू करने के लिए नोडल संगठन होंगे।

खोया और पाया बच्चों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल

इसमें खोया और पाया बच्चों पर वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करने एवं साझा करने में सुविधा होगी, इसे अपराध की जाँच और समय पर प्रतिक्रिया में सुधार करने के लिए एक लम्बा रास्ता तय करना होगा।

रोजगार के लिये आईटी (IT for Jobs)

इस स्तम्भ का ध्यान आईटी/आईटीएस के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने के लिये युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कराने पर केन्द्रित है। इस स्तम्भ के आठ घटक हैं –

रोजगार हेतु आईटी

1. छोटे कस्बों और गाँवों के लोगों के लिए आईटी प्रशिक्षण
2. इस घटक का लक्ष्य 5 वर्षों में आईटी क्षेत्र की नौकरियों के लिए छोटे शहरों और गाँवों के एक करोड़ छात्रों को प्रशिक्षित करना है। डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल विभाग है।
3. पूर्वोत्तर राज्यों में आईटी/आईटीईएस
4. इस घटक का लक्ष्य राज्यों में आईसीटी सक्षम वृद्धि की सुविधा के लिए हर उत्तर–पूर्वी राज्य में बीपीओ की स्थापना पर केन्द्रित है। डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल विभाग है।
5. प्रशिक्षण सेवा डिलिवरी एजेन्ट
6. व्यवहार्य रूप में बिजनेस डिलिवरी और आईटी सेवाओं की पहुँच सुनिचित करने के लिए तीन लाख सेवा डिलिवरी एजेंटों के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित है। डीईआईटीवाई इस योजना के लिए नोडल विभाग है।
7. टेलीकॉम और दूरसंचार से संबंधित सेवाओं पर ग्रामीण श्रमिकों का प्रशिक्षण।
8. इस घटक का ध्यान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाँच लाख ग्रामीण श्रमिकों को दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपीएस) के प्रशिक्षण पर केन्द्रित है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) इस योजना के लिए नोडल विभाग है।

हर जगह मोबाइल कनेक्टिविटी – (Universal access to phones)

इस स्तम्भ का ध्यान देश में नेटवर्क की पहुँच और कनेक्टिविटी के अन्तराल को कम करने पर केन्द्रित है।

देश में करीब 55,619 गाँव ऐसे है जहाँ मोबाइल कवरेज नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लिए व्यापक विकास योजना को ऐसे गाँवों में मोबाइल कवरेज प्रदान कराने के लिए शुरू किया गया है। मोबाइल कवरेज से वंचित गाँवों को चरणबद्ध तरीके से मोबाइल कवरेज मुहैया कराया जाएगा।

दूरसंचार विभाग इस परियोजना के लिए नोडल विभाग होगा और इसकी लागत 2014–18 के दौरान 16,000 करोड़ रुपये के आसपास होगी।

इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण –(Electronic Manufacturing)

इस स्तम्भ आशय का एक असाधारण प्रदर्शन के रूप में 2020 तक नेट शून्य आयात के लक्ष्य के साथ देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केन्द्रित है। इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई क्षेत्रों में समन्वित कार्यवाही की आवश्यकता है, जैसेः

1. कराधान, प्रोत्साहन
2. अर्थव्यवस्था का पैमाना, लागत नुकसान को कम करना
3. फोकस क्षेत्र – बिग टिकट आइटम
   फैक्स, फैब लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसैट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट ऊर्जा मीटर, स्मार्ट कार्ड और माइक्रो–एटीएम।
4. इन्क्यूवेटर, क्लस्टर
5. कौशल विकास, पीएचडी कर रहें छात्रों को प्रोत्साहित करना।
6. सरकारी खरीद

7. सुरक्षा के मानक–अनिवार्य पंजीकरण, प्रयोगशालाओं और लघु उद्योगों के लिए सहायता
8. राष्ट्रीय पुरस्कार, विपणन, ब्राण्ड बिल्डिंग
9. राष्ट्रीय केन्द्र – फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, सुरक्षा बल
10. इलेक्ट्रॉनिक्स में आर एण्ड डी

वर्तमान में चल रहे कई कार्यक्रमों को ठीक से समायोजित किया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मौजूदा ढांचा अपर्याप्त है और इसे मजबूत बनाने की जरूरत है।

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग 22 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ बढ़ती जा रही है और 2020 तक 400 अरब डालर तक पहुँचने की उम्मीद है। भारत सरकार भी इस क्षेत्र में विनिर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है जिससे भारत का निवेश करने के लिए सम्भावित स्थानों की सूची में उच्च स्थान है।

इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति (एनपीई)

भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति को 2012 (एनपीई 12) में मंजूरी दी है, जो भारत में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश के लिए वैश्विक और घरेलू कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में प्रेरित, समग्र और निवेशकों के अनुकूल बाजार उपलब्ध कराती है।

ई–क्रान्ति (E-Kranti)

ई–क्रान्ति, डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। देश में ई–शासन, मोबाइल शासन और सुशासन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तथा गवर्नेन्स के कायाकल्प के लिए ई–गवर्नेन्स का कायाकल्प की दृष्टि से ई–क्रांति के दृटिकोण और प्रमुख घटक को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 25–03–2015 को अनुमोदित किया गया है।

सभी नई और वर्तमान में जारी ई–गवर्नेस परियोजनाओं तथा मौजूदा परियोजनाओं जिनका पुर्नोत्थान किया जा रहा है, अब इन परियोजनाओं को ई–क्रान्ति के प्रमुख सिद्धान्तों अर्थात् परिवर्तन न की रूपान्तरण, एकीकृत सेवाएं न कि व्यक्तिगत सेवाएं, प्रत्येक एमएमपी में सरकारी प्रक्रिया में री–इंजीनियरिंग (जीपीआर) को अनविार्य किया जाना, मांग पर आईसीटी बुनियादी सुविधा, डिफ्रॉल्ट रूप से क्लाउड, मोबाइल प्रथम, फास्ट ट्रैक स्वीकृति, मानक और प्रोटोकॉल अनिवार्य, भाषा स्थानीयकरण, राष्ट्रीय जीआईएस (भू–स्थानिक सूचना प्रणाली), तथा सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डेटा संरक्षण के अनुरूप होना चाहिए।

ई–क्रान्ति के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाएं अपने कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

किसानों के लिए प्रौद्योगिकी

इससे किसानों को वास्तविक समय में कीमत की जानकारी, इनपुट का ऑनलाइन आदेश एवं ऑनलाइन कैश, ऋण और मोबाइल बैकिंग के माध्यम से राहत भुगतान प्राप्त करने में सुविधा होगी।

वित्तीय समावेशन के लिए प्रौद्योगिकी

मोबाइल, बैकिंग, माइक्रो एटीएम प्रोग्राम और सीएससी/डाकघरों का उपयोग कर वित्तीय समावेशन को सदृढ़ किया जाएगा।

साइबर सुरक्षा के लिये प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केन्द्र को देश के भीतर विश्वसनीय और सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाएगा।

शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी – ई–शिक्षा

सभी स्कूलों को ब्रॉडबैण्ड से जोड़ा जाएगा। सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में मुक्त वाई–फाई प्रदान किया जाएगा (यह कवरेज तकरीबन 250,000 स्कूलों तक होगा)। डिजिटल साक्षरता पर एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम लाया जाएगा। ई–शिक्षा के लिए बड़े पैमाने पर आनलाइन ओपन पाठ्यक्रमों का विकास और उद्यामन किया जायेगा।

हेल्थ के लिए प्रौद्योगिकी –ई–हेल्थकेयर

ई–हेल्थकेयर के अन्तर्गत ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श, ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड, दवाओं की ऑनलाइन आपूर्ति, रोगी की जानकारी का पूरे भारत में आदान–प्रदान, आदि को कवर किया जाएगा।

सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी

नागरिकों को समय रहते एहतियाती उपाय करने एवं जीवन और सम्पत्ति के नुकसान को कम करने के लिए मोबाइल आधारित आपातकालीन सेवाएं और आपदा से संबंधित सेवाएं वास्तविक समय के आधार प्रदान की जाएगी।

न्याय के लिए प्रौद्योगिकी

अंतःप्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, को कई संबंधित आवेदनों जैसे ई–न्यायालयों, ई–पुलिस, ई–जेलों और ई–अभियोजना द्वारा सुदृढ़ किया जाएगा।

सभी के लिए सूचना (Information for all)

ओपन डाटा प्लेटफार्म मंत्रालयों/विभागों को उपयोग, पुनः उपयोग और पुनर्वितरण के लिए ओपन प्रारूप में डेटासेट के सक्रिय रीलीज की सुविधा देता है। सूचना और दस्तावेजों की ऑनलाइन होस्टिंग से नागरिकों का ओपन और आसानी से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा होगी।

सरकार सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय रूप से संलग्न करेगी

सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को सूचित करने और उनसे बातचीत करने के लिए सक्रिय रूप से संलग्न करेगी। MyGov.in शासन से नागरिकों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म है, जिसे सरकार के साथ विचारों/सुझावों का आदान–प्रदान करने के माध्यम के रूप में, 26 जुलाई, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। इसमें सुशासन के लिए नागरिकों और सरकार के बीच टू–वे संचार की सुविधा होगी।

ऑनलाइन संदेश

विशेष अवसरों/कार्यक्रमों पर नागरिकों को ऑनलाइन संदेश ई–मेल और एसएमएस के माध्यम से मदद की जा रही है।

ओपन डाटा प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया भागीदारी और ऑनलाइन संदेश के लिए मोटे तौर पर मौजूदा बुनियादी ढांचे और सीमित अतिरिक्त संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता होगी।

इन प्रमुख नौ स्तम्भों में अनेक परियोजनाएं/उत्पाद या तो पहले ही लांच किये जा चुके हैं या लांच किए जाने के लिए तैयार हैं : इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है –

1. **डिजिटल लॉकर प्रणाली** (Digital Locker System) शुरू की गई है जिसका उद्देश्य पंजीकृत संग्राहकों (Registered Depositories) के जरिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ई–दस्तावेजों (e-documents) को सुरक्षित रखना तथा फिजीकल डॉक्यूमेन्ट्स का उपयोग न्यूनतम करना।
2. **डिस्क डू, डिसिमिनेट** अप्रोच के जरिए प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी के लिए My Gov.in एक प्लेटफॉर्म के रूप में लागू की गई है My Gov.in के लिए मोबाइल एप मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा।
3. **स्वच्छ भारत मिशन** (एसबीएम) मोबाइल एप का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जनता और सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकेगा।
4. **आधार प्रमाणिता** (Adhar Authentication) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन दस्तावेजों पर ई–हस्ताक्षर डिजिटल रूप से किए जा सकेंगे।
5. नए शुरू किए गए **ई–हॉस्पिटल** एप्लीकेशन के अधीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ओआरएस) शुरू किया गया है इसके जरिए ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क के भुगतान मिलने के निश्चित समय का निर्धारण (Appointment) ऑनलाइन निदान रिपोर्ट (Online diagnostic reports) रक्त की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी जैसी मुख्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
6. **नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल** से छात्रों के आवेदन–पत्र जमा करने, सत्यापन, स्वीकृति और लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही छात्रवृत्तियों के वितरण तक की प्रक्रिया का एक मुश्त समाधान हो सकेगा।
7. रिकार्डस को व्यापक स्तर पर डिजिटाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी विभाग ने **डिजिटाइज इंडिया प्लेटफार्म** (DIP) नामक एक पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने शुरू की है, जो नागरिकों को कुशल सेवाएं प्रदान करेंगी।
8. भारत सरकार ने **भारत नेट** (Bharat Net) नाम से एक पहल शुरू की है। यह देश की ढाई लाख ग्राम पंचायातें को जोड़ने के लिए उच्चगति का डिजिटल हाईवे है।
9. बीएसएनएल ने 30 वर्ष पुराने एक्सचेंजों को हटाने के लिए **नेस्ट जनरेशन नेटवर्क** (NGN) शुरू किया है, जो वॉयस, डाटा, मल्टीमीडिया/वीडियो और अन्य सभी प्रकार की संचार सेवाओं को नियन्त्रित करने के लिए आईपी आधारित प्रौद्योगिकी है।
10. बीएसएनएल ने देशभर में **वाई–फाई–हॉटस्पोट्स** (Wi-fi-Hotspots) विकसित किए हैं, जहाँ मोबाइल उपकरणों के जरिए बीएसएनएल वाई–फाई नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है।
11. नागरिक सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने और नागरिकों तथा प्राधिकारियों की एक–दूसरे के साथ बातचीत में सुधार लाने के लिए देशव्यापी कनेक्टिविटी की आवश्यकता को महसूस करते हुए **ब्रॉडबैण्ड हाईवे** को डिजिटल इंडिया के एक मुख्य स्तम्भ के रूप में शामिल किया गया है।
12. विभिन पूर्वोत्तर राज्यों में व अन्य राज्यों के छोटे और मुफस्सिल शहरों में **बीपीओ केन्द्र** खोलने के लिए बीपीओ नीति को मंजूरी दी गई है।
13. नवाचार (Innovations) अनुसंधान और विकास (R & D) तथा उत्पाद और विकास को प्रोत्साहन देने उपक्रम निधियों (Venture Funds) की आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने के लिए देश में **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि** (EDF) नीति लाई गई है।
14. फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के उभरते हुए क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए **फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय केन्द्र** (National Centre for Flexible Electronics) स्थापित किया गया है।
15. इंटरनेट ऑन थिंग्स के लिए **उत्कृष्टता केन्द्र** (Centre of Excellence on Internet on Things) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ERNET व नैस्कॉम (NASSCOM) की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया है।

उद्देश्य

हम डिजिटल ताकत को समझे।

महत्व

डिजिटल इंडिया के ये नौ स्तम्भ देश को एकता के सूत्र में बाँधने में सहायक हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कारगर हैं, सर्वत्र पारदर्शिता का वातावरण बनाने में सहायक हैं, कागजी कार्य, समय, मानव श्रम की बचत में मददगार हैं, कार्यकुशलता में सुधार लाने वाले हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से "मेड इन इण्डिया" इलेक्ट्रानिक डिवाइसों, उत्पादकों और सेवाओं के पोर्टफोलियो को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं के लिये रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं।

निष्कर्ष

समय बहुत तेजी से बदल चुका है, समय की मांग है कि हम डिजिटल ताकत को समझें। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सामर्थ्य है उसके साथ आधुनिक विज्ञान को आधुनिक तकनीकी को जोड़ना अनिवार्य है। आज हमारे देश में करीब 25 करोड़ से 30 करोड़ (Internet Users) हैं। Users की संख्या में ये दुनिया में संख्या बड़ी है लेकिन जो इससे वंचित है वो संख्या भी दुनिया के हिसाब से बड़ी है। देश का एक तबका Digital World के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देश का एक बहुत बड़ा तबका उससे वंचित है – निश्चित तौर पर समस्याएं बढ़ेगी – इसलिए आने वाले वर्षों में सभी

को यह प्लेटफार्म उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए हमें अपने आप को सजग करना होगा, व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। हमारे देश के नौजवान अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हुए, " Design In India" को ध्यान में रखते हुए Digital India में नई ताकत, नए प्राण भर सकते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- *प्रतियोगिता दर्पण (अतिरिक्तांक – 2017)*
2- *क्रानिकल वार्षिकी 2017*
3- *इलेक्ट्रनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार (वेबसाइट)*
4- *प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण अंश "डिजिटल इंडिया"*